International Organization of Research & Development (IORD)
ISSN: 2348-0831
Vol 13 Issue 01 | 2025

आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और सामूहिक सुरक्षाः नई वैश्विक चुनौतियों का विश्लेषण

दरवेश (शोधार्थी), डॉ. सुशीला बेदी दुबे (शोध निदेशक)
राजनिति विज्ञान विभाग, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय, चूड़ेला, झुंझुनूं

DOI: https://www.doi.org/10.5281/zenodo.17823757

सारांश

समकालीन वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में आतंकवाद और साइबर खतरों के उदय ने अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता की पारंपरिक धारणाओं को गहन चुनौती दी है। सुरक्षा अब केवल राज्यों की सीमाओं और सैन्य क्षमताओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह सीमा–रहित, अदृश्य और असंगठित रूप में उभरने वाले खतरों से जुड़ चुकी है। इस परिवर्तित संदर्भ में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा, जो मुख्यतः राज्य–केंद्रित संघर्षों को ध्यान में रखकर विकसित हुई थी, अपने उपयोग और प्रभावशीलता को लेकर नए प्रश्नों के घेरे में है।

प्रस्तुत लेख आतंकवाद और साइबर सुरक्षा को समकालीन वैश्विक चुनौतियों के रूप में विश्लेषित करता है और यह परीक्षण करता है कि क्या सामूहिक सुरक्षा का मौजूदा ढाँचा इन बहुआयामी खतरों से निपटने में सक्षम है। लेख का केंद्रीय तर्क यह है कि समकालीन सुरक्षा खतरों की प्रकृतिकृउनकी असममित संरचना, तकनीकी निर्भरता और नेटवर्क आधारित स्वरूपकृसामूहिक सुरक्षा की पारंपरिक समझ से भिन्न है। आतंकवादी संगठनों और साइबर हमलों का संचालन किसी एक राज्य तक सीमित न होकर अंतरराष्ट्रीय ढाँचे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जिससे सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता तो तमअमंसे होती है, परंतु उसका प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाता।

यह अध्ययन यह भी इंगित करता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और सामूहिक सुरक्षा तंत्र तेजी से बदलते सुरक्षा वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालने में असमर्थ रहे हैं। साइबर हमलों और आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भ में न तो स्पष्ट उत्तरदायित्व तय हो पाता है और न ही सामूहिक कार्रवाई की सर्वसम्मत रणनीति विकसित हो पाती है। लेख का निष्कर्ष यह प्रतिपादित करता है कि वर्तमान वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को एक नए, लचीले और समन्वित ढाँचे में पुनर्व्याख्यायित करना अनिवार्य हो गया है।

1 वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में नई चुनौतियों का उभार

इक्कीसवीं शताब्दी में वैश्विक सुरक्षा की प्रकृति में मौलिक परिवर्तन दिखाई देता है। पारंपरिक काल में सुरक्षा का आशय मुख्यतः सैन्य आक्रमण, सीमा विवाद और राज्यों के बीच युद्ध से जुड़ा हुआ था, किंतु वर्तमान समय में सुरक्षा संबंधी खतरे अधिक जटिल, बहुआयामी और सीमा–रहित बन गए हैं। इन चुनौतियों ने न केवल राष्ट्रों की आंतरिक स्थिरता को प्रभावित किया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को भी अस्थिर बना दिया है।

समकालीन सुरक्षा खतरों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी असममित प्रकृति है। आतंकवाद और साइबर हमले किसी निर्धारित भू–सीमा या पारंपरिक युद्ध के नियमों का पालन नहीं करते। ये खतरे गैर–राज्य तत्वों, तकनीकी नेटवर्कों और वैचारिक संगठनों के माध्यम से विकसित होते हैं, जिससे पारंपरिक सुरक्षा तंत्र इन्हें पहचानने और नियंत्रित करने में असफल सिद्ध होते हैं। परिणामस्वरूप, सुरक्षा अब केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि सूचना, तकनीक और वैश्विक सहयोग से भी जुड़ गई है।

आतंकवाद ने जिस प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया है, उसने सुरक्षा की अवधारणा को राज्य–केंद्रित दृष्टिकोण से हटाकर समाज–केंद्रित बना दिया है। नागरिक आबादी को निशाना बनाना, भय का प्रसार और सीमाओं के पार संचालन इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। इसी प्रकार साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्ध अब केवल भूमि, जल और आकाश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल क्षेत्र भी संघर्ष का नया मंच बन चुका है।

इन नई चुनौतियों का उभार यह संकेत देता है कि वैश्विक सुरक्षा अब एक सतत प्रक्रिया बन चुकी है, जिसमें खतरे आकस्मिक नहीं, बल्कि निरंतर और परिवर्तनशील होते हैं। ऐसी स्थिति में परंपरागत सुरक्षा ढाँचे और सामूहिक सुरक्षा की मौजूदा संरचनाएँ पर्याप्त प्रतीत नहीं होतीं। इन खतरों से निपटने के लिए न केवल नीतिगत समन्वय की आवश्यकता है, बल्कि सुरक्षा की अवधारणा को भी व्यापक और लचीले स्वरूप में पुनर्संरचित करना अनिवार्य हो गया है।

2 आतंकवादः राज्य–सीमाओं से परे उभरता हुआ वैश्विक खतरा

आतंकवाद समकालीन वैश्विक सुरक्षा के समक्ष उपस्थित सबसे जटिल और निरंतर विकसित होने वाली चुनौती के रूप में उभरा है। इसकी प्रकृति पारंपरिक संघर्षों से भिन्न है, क्योंकि यह किसी एक राज्य, भू–क्षेत्र या नियमित सैन्य ढाँचे तक सीमित नहीं रहता। आतंकवादी गतिविधियाँ सीमा–रहित संचालन, गुप्त नेटवर्क और वैचारिक प्रेरणाओं के माध्यम से संचालित होती हैं, जिससे इन्हें नियंत्रित करना अत्यंत कठिन हो जाता है।

आतंकवाद की मुख्य चुनौती इस तथ्य में निहित है कि यह सीधे नागरिक समाज को लक्षित करता है। भय और असुरक्षा का प्रसार इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, जिससे शासन व्यवस्था, सामाजिक विश्वास और राज्य की वैधता प्रभावित होती है। इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा अब केवल राष्ट्रीय रक्षा का विषय न रहकर सामाजिक स्थिरता और मानवीय सुरक्षा से भी गहराई से जुड़ जाती है।

समकालीन आतंकवाद का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष उसका वैश्विक स्वरूप है। आतंकवादी संगठन विभिन्न देशों में फैले सहयोगी तंत्रों, वित्तीय स्रोतों और संचार माध्यमों के माध्यम से कार्य करते हैं। यह वैश्विक विस्तार सुरक्षा को एक साझा समस्या बनाता है, किंतु अभ्यास में राज्यों की प्रतिक्रियाएँ प्रायः राष्ट्रीय हितों तक सीमित रह जाती हैं। ऐसे में सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकता स्पष्ट रूप से उभरती है, परंतु उसका प्रभावी क्रियान्वयन जटिल हो जाता है।

आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक प्रतिक्रिया में सबसे बड़ी बाधा यह है कि इसकी पहचान और जिम्मेदारी तय करना कठिन होता है। जब खतरा किसी एक राज्य से प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता, तब पारंपरिक प्रतिरोध और दंडात्मक कार्रवाई कारगर नहीं रह जाती। परिणामस्वरूप, आतंकवाद से निपटने में सैन्य कार्रवाई के साथ–साथ राजनीतिक सहयोग, खुफिया समन्वय और वैचारिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार आतंकवाद यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान वैश्विक सुरक्षा संकट पारंपरिक संघर्षों से आगे बढ़ चुका है। यह न केवल सामूहिक सुरक्षा की सीमाओं को उजागर करता है, बल्कि सुरक्षा ढाँचों में गहन परिवर्तन की माँग भी करता है। आतंकवाद के संदर्भ में सुरक्षा अब साझा उत्तरदायित्व की अवधारणा तो प्रस्तुत करती है, किंतु उसकी संरचनात्मक अपर्याप्तता भी समान रूप से उजागर करती है।

3 साइबर सुरक्षाः अदृश्य लेकिन व्यापक वैश्विक खतरे का उदय

डिजिटल प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने वैश्विक समाज को अभूतपूर्व सुविधा और परस्पर जुड़ाव प्रदान किया है, किंतु इसके साथ ही सुरक्षा संबंधी नई और जटिल चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। साइबर सुरक्षा आज केवल तकनीकी समस्या न रहकर एक गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक प्रश्न बन चुकी है। इसके अंतर्गत होने वाले हमले प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, फिर भी इनके प्रभाव व्यापक, गहरे और दीर्घकालिक होते हैं।

साइबर खतरों की सबसे विशिष्ट विशेषता उनका अदृश्य स्वरूप है। पारंपरिक सुरक्षा खतरों की तुलना में साइबर हमले बिना किसी भौगोलिक सीमा का उल्लंघन किए ही राज्य की संप्रभुता, संस्थागत संरचना और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। सरकारी तंत्र, वित्तीय प्रणाली, संचार नेटवर्क और आवश्यक सेवाएँ इस प्रकार के हमलों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो चुकी हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक युद्ध और संघर्ष अब केवल सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं रहे हैं।

साइबर सुरक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष जिम्मेदारी निर्धारण की जटिलता है। किसी साइबर हमले के स्रोत की पहचान करना कठिन होता है, जिससे यह तय करना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि आक्रामक कौन है और प्रतिक्रिया किस पर की जाए। यह स्थिति सामूहिक सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा को सीधे

चुनौती देती है, क्योंकि सामूहिक प्रतिक्रिया सामान्यतः स्पष्ट आक्रमण और आक्रामक की पहचान पर आधारित होती है।

इसके अतिरिक्त, साइबर क्षेत्र में राज्य और गैर–राज्य तत्वों के बीच की रेखाएँ धुंधली हो जाती हैं। निजी समूह, संगठित अपराध नेटवर्क और वैचारिक संगठन साइबर माध्यमों का उपयोग कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रतिक्रिया केवल राज्य–केंद्रित नहीं रह सकती, बल्कि बहु–स्तरीय सहयोग की माँग करती है। किंतु व्यवहार में सामूहिक सुरक्षा तंत्र इस प्रकार के लचीले और त्वरित समन्वय को विकसित करने में पिछड़ा दिखाई देता है।

साइबर सुरक्षा के संदर्भ में यह भी देखा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों और सहमत मानकों का अभाव बना हुआ है। क्या साइबर हमला युद्ध के समान माना जाएकृइस प्रश्न पर वैश्विक सहमति का न होना सामूहिक सुरक्षा को और कमजोर करता है। परिणामस्वरूप, कई बार राज्य एकतरफा उपायों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे सहयोग की भावना प्रभावित होती है।

इस प्रकार साइबर सुरक्षा समकालीन वैश्विक सुरक्षा का वह पक्ष है जो न केवल अदृश्य है, बल्कि सामूहिक सुरक्षा की संरचनात्मक सीमाओं को भी उजागर करता है। यह चुनौती संकेत देती है कि यदि सामूहिक सुरक्षा को प्रासंगिक बनाए रखना है, तो उसे तकनीकी यथार्थ और नए प्रकार के खतरों के अनुरूप स्वयं को पुनर्संरचित करना होगा।

4 आतंकवाद और साइबर खतरेः सामूहिक सुरक्षा के लिए संयुक्त और जटिल चुनौती

आतंकवाद और साइबर सुरक्षा को यदि अलग–अलग सुरक्षा समस्याओं के रूप में देखा जाए, तो समकालीन वैश्विक खतरे की वास्तविक प्रकृति को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। वर्तमान समय में ये दोनों चुनौतियाँ परस्पर जुड़कर एक ऐसे सुरक्षा संकट का निर्माण कर रही हैं, जो पारंपरिक सामूहिक सुरक्षा ढाँचों की सीमाओं को और अधिक स्पष्ट कर देता है। आतंकवादी संगठनों द्वारा साइबर माध्यमों का बढ़ता उपयोग इस संयुक्त खतरे का सबसे स्पष्ट प्रमाण है।

आधुनिक आतंकवाद केवल भौतिक हिंसा तक सीमित नहीं रहा है। साइबर माध्यमों के उपयोग से आतंकवादी संगठन भर्ती, प्रचार, वित्त जुटाने और समन्वय जैसे कार्यों को वैश्विक स्तर पर संचालित करने लगे हैं। इससे आतंकवाद की पहुँच और प्रभाव दोनों में वृद्धि हुई है। यह परिवर्तन सुरक्षा तंत्र के लिए गंभीर चुनौती बनता है, क्योंकि खतरा अब प्रत्यक्ष युद्धभूमि के बजाय डिजिटल और सामाजिक क्षेत्रों में फैल चुका है।

साइबर हमले और आतंकवादी हिंसा का यह संयोजन सामूहिक सुरक्षा की प्रतिक्रिया क्षमता को जटिल बनाता है। एक ओर आतंकवादी गतिविधियाँ त्वरित और असममित प्रतिक्रिया की माँग करती हैं, वहीं दूसरी ओर साइबर खतरों के संदर्भ में पहचान, प्रमाण और उत्तरदायित्व तय करना समयसाध्य प्रक्रिया बन जाता है। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से यह तय करना कठिन हो जाता है कि सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत किस प्रकार और किस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाए।

इसके अतिरिक्त, इस संयुक्त खतरे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सुरक्षा को केवल राज्य–केंद्रित ढाँचे में सीमित नहीं रहने देता। राज्य, निजी क्षेत्र, तकनीकी संस्थान और नागरिक समाज सभी इस चुनौती से प्रभावित होते हैं। किंतु सामूहिक सुरक्षा की मौजूदा संरचना मुख्यतः राज्यों के बीच सहयोग पर आधारित है, जिससे यह बहु–स्तरीय संकट के समाधान में अपर्याप्त प्रतीत होती है।

आतंकवाद और साइबर खतरे का यह संयुक्त स्वरूप यह संकेत देता है कि समकालीन सुरक्षा चुनौतियाँ अलग–अलग खाँचों में रखकर नहीं समझी जा सकतीं। ये एक–दूसरे को सशक्त करने वाली शक्तियाँ बन चुकी हैं। इस स्थिति में सामूहिक सुरक्षा को न केवल अपनी प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ानी होगी, बल्कि सुरक्षा की परिभाषा को भी व्यापक बनाना होगा, ताकि यह बदलते खतरे के स्वरूप को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सके।

5 सामूहिक सुरक्षा की संरचनात्मक सीमाएँ और संस्थागत कमजोरियाँ

आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसी नई चुनौतियों के संदर्भ में सामूहिक सुरक्षा की प्रभावशीलता पर विचार करते समय इसकी संरचनात्मक सीमाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा मूलतः उस कालखंड में विकसित हुई थी, जब सुरक्षा खतरे मुख्यतः राज्यों के बीच सैन्य संघर्षों

तक सीमित थे। वर्तमान वैश्विक परिवेश में खतरे की प्रकृति बदल जाने के बावजूद इसका संस्थागत ढाँचा अपेक्षाकृत अपरिवर्तित बना हुआ है।

सामूहिक सुरक्षा तंत्र की सबसे प्रमुख सीमा उसकी निर्णय–प्रक्रिया में निहित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक कार्रवाई व्यापक सहमति पर आधारित होती है, किंतु आतंकवाद और साइबर हमलों जैसी स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया अत्यंत आवश्यक होती है। सहमति की लंबी प्रक्रिया सुरक्षा हस्तक्षेप को विलंबित करती है, जिससे संकट और अधिक गहरा हो सकता है। इस प्रकार, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता और संस्थागत प्रक्रिया के बीच असंतुलन स्पष्ट दिखाई देता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण कमजोरी उत्तरदायित्व निर्धारण से जुड़ी है। जब कोई आक्रमण स्पष्ट रूप से किसी एक राज्य से नहीं जुड़ा होता, तब सामूहिक सुरक्षा तंत्र के लिए यह तय करना कठिन हो जाता है कि किसके विरुद्ध और किस प्रकार की कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से साइबर हमलों और आतंकवादी नेटवर्कों के संदर्भ में यह अस्पष्टता सामूहिक प्रतिक्रिया को कमजोर बना देती है।

इसके अतिरिक्त, सामूहिक सुरक्षा की संरचना राज्य–केंद्रित सोच पर आधारित है, जबकि समकालीन सुरक्षा चुनौतियाँ गैर–राज्य तत्वों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। आतंकवादी संगठन, साइबर अपराधी समूह और वैचारिक नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के औपचारिक ढाँचों से बाहर कार्य करते हैं। सामूहिक सुरक्षा तंत्र इन नए अभिनेताओं से निपटने के लिए पर्याप्त लचीलापन और साधन विकसित नहीं कर पाया है।

इन संस्थागत सीमाओं के कारण सामूहिक सुरक्षा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे संकटों में न तो पूर्णतः विफल कही जा सकती है और न ही पूर्णतः सफल। यह एक संक्रमणकालीन स्थिति में दिखाई देती हैकृजहाँ इसकी मूल भावना अब भी प्रासंगिक है, किंतु इसका वर्तमान स्वरूप बदलते खतरों से तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहा है। यही कारण है कि सामूहिक सुरक्षा की पुनर्संरचना और संस्थागत सुधार पर गंभीर विमर्श अनिवार्य हो गया है।

6 नई वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में सामूहिक सुरक्षा की पुनर्व्याख्या

आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसी समकालीन चुनौतियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सामूहिक सुरक्षा की पारंपरिक परिभाषा अब अपर्याप्त हो चुकी है। जिस अवधारणा को मुख्यतः राज्यों के बीच सैन्य आक्रमणों को रोकने के लिए निर्मित किया गया था, वह आज ऐसे खतरों का सामना कर रही है जो न तो भौगोलिक सीमाओं का सम्मान करते हैं और न ही पारंपरिक युद्ध के ढाँचों का पालन करते हैं। इस परिस्थिति में सामूहिक सुरक्षा की पुनर्व्याख्या एक सैद्धांतिक आवश्यकता भर नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनिवार्यता बन गई है।

नई वैश्विक चुनौतियाँ यह संकेत देती हैं कि सुरक्षा को अब केवल सैन्य शक्ति या क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आतंकवादी हिंसा और साइबर हमले सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर भी प्रभाव डालते हैं। अतः सामूहिक सुरक्षा को मानवीय सुरक्षा, सूचना सुरक्षा और तकनीकी सतर्कता को अपने दायरे में सम्मिलित करना होगा। यह परिवर्तन सुरक्षा की राज्य–केंद्रित सोच से बहु–आयामी दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है।

पुनर्व्याख्या का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सामूहिक सुरक्षा को प्रतिक्रियात्मक की जगह निवारक स्वरूप प्रदान किया जाए। अब केवल संकट उत्पन्न होने के बाद प्रतिक्रिया देना पर्याप्त नहीं हैय इसके स्थान पर खतरों की समयपूर्व पहचान, साझा खुफिया सहयोग और तकनीकी निगरानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आतंकवाद और साइबर खतरों के संदर्भ में यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, सामूहिक सुरक्षा की पुनर्व्याख्या में गैर–राज्य तत्वों की भूमिका को भी समझना अनिवार्य है। वर्तमान वैश्विक सुरक्षा चुनौतियाँ केवल राज्यों के माध्यम से उत्पन्न नहीं होतीं, इसलिए केवल राज्यों के बीच सहयोग पर आधारित सुरक्षा ढाँचा सीमित सिद्ध होता है। निजी क्षेत्र, तकनीकी संस्थान और नागरिक समाज की भागीदारी के बिना सामूहिक प्रयास अधूरे रह जाते हैं।

इस प्रकार नई वैश्विक चुनौतियाँ सामूहिक सुरक्षा को स्थिर अवधारणा के बजाय एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखने की माँग करती हैं। यदि सामूहिक सुरक्षा को आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे खतरों के संदर्भ में प्रभावी बनाना है, तो इसकी परिभाषा, उद्देश्य और साधनों में मूलभूत परिवर्तन आवश्यक हो चुका है।

7 संयुक्त वैश्विक प्रतिक्रिया की संभावनाएँ और उसकी सीमाएँ

आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियाँ स्वभावतः ऐसी हैं जिनका समाधान किसी एक राज्य की क्षमता से परे है। इन खतरों की सीमा–रहित प्रकृति यह संकेत देती है कि प्रभावी उत्तर केवल संयुक्त वैश्विक प्रयासों के माध्यम से ही संभव है। इस संदर्भ में सामूहिक सुरक्षा एक आवश्यक मंच प्रदान करती है, जहाँ सहयोग, सूचना–विनिमय और साझा रणनीति विकसित की जा सकती है। किंतु व्यवहारिक स्तर पर इस संयुक्त प्रतिक्रिया की संभावनाएँ और सीमाएँ दोनों ही समान रूप से सामने आती हैं।

संयुक्त वैश्विक प्रतिक्रिया की सबसे बड़ी संभावना साझा जानकारी और समन्वय में निहित है। आतंकवादी नेटवर्कों और साइबर खतरों का समय रहते पता लगाने के लिए विभिन्न देशों के बीच खुफिया सहयोग और तकनीकी सूचनाओं का आदान–प्रदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब ऐसे प्रयास प्रभावी रूप से किए जाते हैं, तो सामूहिक सुरक्षा वास्तविक रूप में निवारक भूमिका निभा सकती है। कुछ क्षेत्रों में यह सहयोग आंशिक रूप से सफल भी रहा है।

इसके बावजूद, संयुक्त प्रतिक्रिया की राह में गंभीर बाधाएँ विद्यमान हैं। राज्यों के बीच विश्वास का अभाव, संवेदनशील सूचनाएँ साझा करने में संकोच और तकनीकी असमानताएँ सहयोग को सीमित कर देती हैं। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में यह समस्या और गहरी हो जाती है, क्योंकि तकनीकी क्षमताएँ सभी देशों में समान नहीं हैं। परिणामस्वरूप वैश्विक प्रतिक्रिया असंतुलित और असमान बन जाती है।

राजनीतिक मतभेद भी संयुक्त कार्रवाई में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। आतंकवाद की परिभाषा, साइबर हमले की गंभीरता और प्रतिक्रिया की वैधता को लेकर राज्यों के दृष्टिकोण भिन्न–भिन्न होते हैं। ऐसे मतभेद सामूहिक रणनीति के निर्माण में विलंब और कमजोर निर्णयों का कारण बनते हैं।

कुल मिलाकर, संयुक्त वैश्विक प्रतिक्रिया आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने का एक आवश्यक माध्यम तो प्रदान करती है, किंतु यह किसी स्वतःसिद्ध समाधान के रूप में कार्य नहीं करती। इसकी प्रभावशीलता राजनीतिक इच्छा, तकनीकी समानता और पारस्परिक विश्वास पर निर्भर करती है। यही कारण है कि सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत संयुक्त प्रतिक्रिया की संभावनाओं के साथ–साथ उसकी सीमाओं को भी यथार्थपरक दृष्टि से स्वीकार करना आवश्यक है।

8 भविष्य की सामूहिक सुरक्षाः अनुकूलन और नवाचार की अनिवार्यता

आतंकवाद और साइबर सुरक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य की वैश्विक सुरक्षा उसी ढाँचे पर आधारित नहीं रह सकती, जो पारंपरिक सैन्य संघर्षों के लिए निर्मित किया गया था। बदलते खतरे सुरक्षा नीतियों से निरंतर अनुकूलन और नवाचार की माँग करते हैं। ऐसे परिवेश में सामूहिक सुरक्षा को एक स्थिर व्यवस्था के बजाय एक विकसित होती प्रक्रिया के रूप में समझना आवश्यक हो गया है।

भविष्य की सामूहिक सुरक्षा का पहला आधार होगाकृलचीलापन। सुरक्षा तंत्र को इस प्रकार विकसित करना होगा कि वह उभरते खतरों की पहचान समय रहते कर सके और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता रखे। आतंकवादी गतिविधियाँ और साइबर हमले आकस्मिक होते हैं, अतः सुरक्षा रणनीतियों को पूर्व–नियोजित सैन्य प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर सतत निगरानी और जोखिम–आकलन पर आधारित होना होगा।

दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है तकनीकी नवाचार का समावेश। साइबर खतरों से निपटने के लिए केवल नीतिगत घोषणाएँ पर्याप्त नहीं हैंय इसके लिए साझा तकनीकी मानक, डिजिटल निगरानी तंत्र और विशेषज्ञ सहयोग को सामूहिक सुरक्षा की संरचना में शामिल करना होगा। यदि तकनीक को केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित रखा गया, तो वैश्विक खतरों का समाधान अधूरा रह जाएगा।

इसके अतिरिक्त भविष्य की सामूहिक सुरक्षा को पूर्वरोकथाम पर केंद्रित होना होगा। केवल किसी हमले के बाद प्रतिक्रिया देने के स्थान पर ऐसी व्यवस्थाएँ विकसित करनी होंगी, जो आतंकवाद और साइबर हमलों के स्रोतों को प्रारंभिक चरण में ही निष्क्रिय कर सकें। यह दृष्टिकोण सामूहिक सुरक्षा को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बना सकता है।

इस प्रकार भविष्य की सामूहिक सुरक्षा का स्वरूप अनुकूलन, तकनीकी नवाचार और सहयोग पर आधारित होना चाहिए। यदि यह परिवर्तन संभव हो पाता है, तो सामूहिक सुरक्षा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसी नई वैश्विक चुनौतियों से निपटने में एक सार्थक भूमिका निभा सकती है।

9 निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसी नई वैश्विक चुनौतियों ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणाओं को गहराई से प्रभावित किया है। सुरक्षा अब केवल राज्यों के बीच सैन्य संघर्षों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह सीमा–रहित, तकनीक–आधारित और असममित खतरों से जुड़ चुकी है। इस बदलती प्रकृति के कारण सामूहिक सुरक्षा का पारंपरिक ढाँचा अपनी प्रभावशीलता और प्रासंगिकता के संदर्भ में गंभीर परीक्षा से गुजर रहा है।

आतंकवाद ने जहाँ राज्य–केंद्रित सुरक्षा सोच को कमजोर किया है, वहीं साइबर खतरों ने यह सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक सुरक्षा संघर्ष अदृश्य लेकिन अत्यंत व्यापक हो सकते हैं। इन दोनों चुनौतियों का संयुक्त स्वरूप सामूहिक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जटिल स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि इनमें न तो आक्रामक की पहचान सरल होती है और न ही प्रतिक्रिया की सीमा स्पष्ट रहती है। परिणामस्वरूप, सामूहिक सुरक्षा अक्सर निर्णायक हस्तक्षेप के बजाय सीमित और प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया तक सिमट जाती है।

इस अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि सामूहिक सुरक्षा की मूल भावनाकृसाझा उत्तरदायित्व और संयुक्त प्रतिक्रियाकृआज भी प्रासंगिक बनी हुई है, किंतु इसका संस्थागत स्वरूप और कार्यप्रणाली समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं रही है। बदलते सुरक्षा परिदृश्य में इसकी उपयोगिता तभी बनी रह सकती है, जब इसे लचीला, तकनीकी रूप से सुदृढ़ और बहु–स्तरीय सहयोग पर आधारित बनाया जाए।

अतः यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के युग में सामूहिक सुरक्षा को न तो पूरी तरह अपर्याप्त मानकर त्यागा जा सकता है और न ही उसे उसके पारंपरिक रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसकी सार्थकता इसके पुनर्गठन, नवाचार और समकालीन वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप अनुकूलन पर निर्भर करती है। यदि यह परिवर्तन संभव हो सका, तो सामूहिक सुरक्षा भविष्य की वैश्विक शांति व्यवस्था में एक प्रभावी और प्रासंगिक भूमिका निभा सकती है।